आपदा प्रबंधन

सजगता, सतर्कता, राहत, बचाव और पुनर्वास का समग्र दृष्टिकोण

एप्रोच : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण लाया गया है।

महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय

- अर्ली वार्निंग एवं पूर्व तैयारी आधारित
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना
- "पहले से तैनाती" रिस्पॉन्स फोर्स
- डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
- समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन
- आपदा निधि का वैज्ञानिक वितरण

आपदा प्रबंधन में बड़ी सफलता

- एक मजबूत अर्ली वार्निंग तथा फर्स्ट रेस्पोंडर व्यवस्था लागू करने में सफलता, जिसका लाभ न केवल भारत को, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों को भी हो रहा है।
- हमारे प्रयासों से चक्रवातों के कारण जानमाल के नुकसान में लगभग 98% की कमी आई है।
- इसी तरह, हमने लू (Heat Wave) से संबंधित मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी हासिल की।
- COVID के बीच में भी, जब हमारी कई महत्त्वपूर्ण संपत्तियाँ जैसे ऑक्सीजन उत्पादक इकाइयाँ चक्रवात प्रभावी क्षेत्र में थीं, तो सिस्टम ने प्रभावी ढंग से रिस्पॉन्स दिया है।
- जून 2016 में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) शुरू की।
  - आपदा प्रबंधन सम्बन्धी सभी एजेंसियों और विभागों के बीच होरिजेंटल एवं वर्टीकल एकीकरण कर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को एक मैट्रिक्स प्रारूप में भी निर्धारित किया गया है।
- 13 जून 2023 को राज्यों और UTs के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश में आपदा प्रबंधन के लिए ₹8000 करोड़ की तीन प्रमुख योजनाओं की घोषणा की
  - राज्यों में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए ₹5,000 करोड़ रुपए की परियोजना
  - शहरों में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले सात महानगरों - मुंबई, चेन्नई, कोलकाता बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे - के लिए ₹2,500 करोड़ की परियोजना, और,
  - भू-स्खलन शमन के लिए 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ₹825 करोड़ की राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम शमन परियोजना
- राष्ट्रीय आपदा मोचन रिज़र्व (NDRR) की स्थापना
  - तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अपेक्षित सामग्री सूची को तैयार करने रखने के लिए ₹250 करोड़ के रेवोल्विंग फंड के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन रिज़र्व (NDRR) की स्थापना।
- NDRF बल की "सक्रिय उपलब्धता": "पहले से तैनाती" की नीति के तहत राज्यों में
  - तत्काल राहत प्रदान करने के लिए NDRF की 2014 के बाद से 06 अतिरिक्त वाहिनियों की स्थापना की
  - NDRF में 16 प्रचालनात्मक वाहिनियां हैं
  - NDRF की टीमें देश के 28 शहरों में रीजनल रेस्पोंस सेंटर के रूप में
  - NDRF की टीम की मौजूदगी और उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को सुचारू किया
  - सभी राज्यों में SDRF का गठन : लगभग सभी राज्यों में एसडीआरएफ का या तो गठन हो चुका है या राज्य पुलिस/होमगार्ड आदि से आपदा मोचन का विशिष्ट कार्य कर रहे हैं

- आपदा निधि वितरण : वैज्ञानिक प्रोसेस के तहत वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक,
  - फरवरी, 2021 में नेशनल डिजास्टर मिटीगेशन फण्ड (NDMF) का गठन किया।
  - NDMF के अंतर्गत ₹13,693 करोड़ की धनराशि का आवंटन; और
  - राज्य डिजास्टर मिटीगेशन निधि (SDMF) के अंतर्गत ₹32,031 करोड़ ।

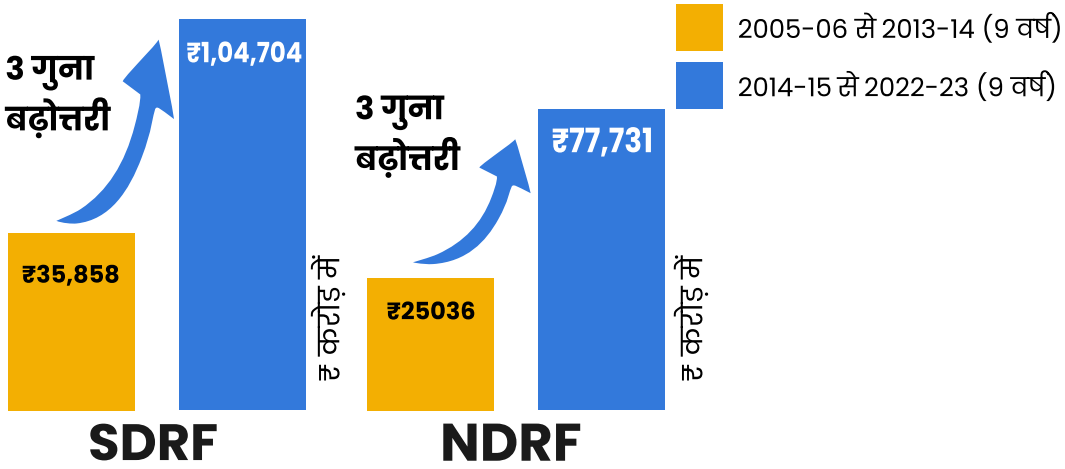

- प्रोएक्टिव IMCT भेजना
  - आज प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद और राज्य सरकार के ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना ही, IMCT को भेजा जा रहा है।
  - पिछले 4 वर्षों में विभिन्न राज्यों में 73 IMCT टीम भेजी गयी है और इन्हें अब 10 दिनों के अन्दर भेज दिया जाता है।

- IDRN (इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क) : एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक सूची है।
  - 01 जनवरी 2022 और 11 जून 2023 के बीच 2,99,121 नए रिकॉर्ड अद्यतन किए गए हैं।

- एन.डी.आर.एफ. अकादमी की स्थापना: माननीय गृह मंत्री के द्वारा 02 जनवरी 2020 को नागपुर में एन.डी.आर.एफ. की आधारशिला रखी गई।

- आपदा मित्र योजना:
  - 'आपदा मित्र स्कीम' को 350 बहु-जोखिम आपदा संभावित जिलों में लागू किया गया है
  - जिसका लक्ष्य 1 लाख से ज्यादा युवा Volunteers को प्रशिक्षित किया जाना है।
  - इन सभी का सरकार द्वारा जीवन बीमा भी किया जाएगा।
  - अब तक 83,024 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
  - कुल ₹369 करोड़ के परिव्यय के साथ आपदा मित्र योजना अनुमोदित की गई

आपदा प्रबंधन अब एक सरकारी काम नहीं है, बल्कि ये 'सबका प्रयास' का एक मॉडल बन गया है

***- श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)*

- कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकोल (सी.ए.पी.): आकास्मिकता/आपदा के संबंध में मोबाइल फोन के जरिए भौगोलिक आधारित तत्काल अलर्ट मुहैया कराने हेतु मार्च 2021 में ₹354 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया। इस प्लेटफार्म का IMD मुख्यालय (+29 केंद्र), CWC मुख्यालय INCOIS मुख्यालय और DGRE के साथ एकीकरण पूर्ण हो चुका है। इसके साथ साथ एफ एस आई, सेटेलाईट रिसीवर (गगन ओ नाविक) और दूर संचार सेवा प्रदाता के साथ भी एकीकरण पूर्ण हो चुका है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकोल (सी.ए.पी.) का Coastal Siren के लिए proof of concept और Google के साथ एकीकरण प्रगति पर है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनआइडीएमएस) पोर्टल - पोर्टल का आरंभ आपदा नुकसान पर क्षेत्रवार डेटा एकत्र करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) के चार (04) लक्ष्यों के तहत विभिन्न संकेतकों पर प्रगति की निगरानी हेतु एक व्यापक ऑनलाइन मॉड्यूल के विकास के लिए किया गया है।
- आपदा आपातकालीन स्थिति के लिए 41 करोड़ रुपये के परिव्यय से 'डायल 112' इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन्स नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (IUIN-DRR-NIDM) की स्थापना की गयी। अब तक, 251 विश्वविद्यालयों को आईयूआईएनडीआरआर में जोड़ा गया है।
- भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया है।
- 'राज्यों के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के रख-रखाव की व्यवस्था हेतु' एक आदर्श विधेयक : गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को 16 सितम्बर 2019 तक भेजा गया है।
- मोबाइल एप्लीकेशन
  - मौसम - आम जनता के लिए दैनिक मौसम की जानकारी, पूर्वानुमान और चक्रवात, भारी वर्षा, गर्मी की लहर, शीत लहर आदि एवं गंभीर मौसम की चेतावनी के लिए
  - मेघदूत - किसानों द्वारा मौसम आधारित कृषि प्रबंधन के लिए
  - दामिनी - बिजली चेतावनी के लिए जो 15 भाषाओ में उपलब्ध है
  - एक विशेष एप क्राउडसोर्सिंग मौसम की जानकारी के लिए

देश में कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार की आपदा आती है और लोगों को पता चलता है कि एनडीआरएफ़, एसडीआरएफ़ आ गया है, तो उनकी आधी चिंता समाप्त हो जाती है।

- श्री अमित शाह *(माननीय गृह मंत्री)*

इनमें से **8 गाइडलाइन्स पिछले 4 वर्षों में बनाई** गई है...

- शीत लहर और फ्रॉस्ट
- भूकंप से सुरक्षा
- छत को ठंडा करने के लिए हाउस ओनर्स गाइड
- ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ)
- हीट वेव गाइडलाइन्स के साथ-साथ एक्शन प्लान भी
- भूस्खलन जोखिम
- दिव्यन्गता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण
- आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय
- 2019 में दिव्यांग Inclusive Disaster Risk Reduction नामक गाइडलाइन्स

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रीस्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीआरआर): नवंबर, 2016 के दौरान नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर 10 सूत्रीय एजेंडा की घोषणा की।

कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) की स्थापना :

- भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए ₹480 करोड़, की वित्तीय सहायता देने की वचनबद्धता की है।
- 31 देश और 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन इस गठबंधन में शामिल हुए हैं।
- सीडीआरआई की अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने दे लिए कैबिनेट के निर्णय के आलोक मे दिनांक 22 अगस्त 2022 को सीडीआरआई और भारत सरकार के मध्य "मुख्यालय समझौता" पर हस्ताक्षर किए गए।

अन्तर्राष्ट्रीय आपदा बचाव के संयुक्त राष्ट्र के मानकों को पूरा करते हुए NDRF INSARAG (International Search & Rescue Advisory Group) से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, जो बल को संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों पर खोज और बचाव कार्यों को करने में सक्षम बनाएगा।

फरवरी 2023: बड़े पैमाने पर भूकंप से तबाह तुर्की के प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक उपकरणों के साथ एनडीआरएफ के 151 कर्मियों वाली तीन टीमों को तुर्की भेजा गया था।